

PCSCRACKER.COM

UPPCS PRELIMS 2017

POLITY-राजव्यवस्था

SHIV KUMAR SINGH

2017

भारतीय संविधान की धारा : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

For More Book Download Click Here - <http://GKTrickHindi.com>

शिव कुमार सिंह का सन्देश

देखिये हम गांव से है ,और हमारे सामने अध्ययन का क्षेत्र ही एक मात्र विकल्प होता है अगर हम इस क्षेत्र में भी पूरी लगन व निष्ठा से नहीं लगेंगे तो निःसंदेह हमारी स्थितियां कभी नहीं बदलेंगी और हमारा भविष्य अतीत की तरह ही हार वाला बना रहेगा ..

एक बात मैं जो आप से कहना चाहता हू वो ये की , आप के अंदर दम है बस आप करने की ठान लीजिये

मुझे यकीं है आप की जीत निश्चित है बस आप रणभूमि में उतर कर बिगुल तो बजाइये ..

मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हू

पृष्ठों की इन शृंखला को रट जाइये और ये मान के चलिये की कम से कम इससे ५ प्रश्न तो आ ही जाएंगे

भारतीय संविधान की धारा : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

- भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं— 444
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा— अनुच्छेद-1
- किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं— अनुच्छेद 12-35
- किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है— अनुच्छेद 5-11
- नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन-सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है— अनुच्छेद-16
- संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति-निर्देशक तत्वों का उल्लेख है— अनुच्छेद 36-51
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है— अनुच्छेद-39
- संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है— अनुच्छेद-61
- किस अनुच्छेद में मंत्रिगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं— अनुच्छेद-75

- महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है— अनुच्छेद-76
- संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है— अनुच्छेद-85
- किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है— अनुच्छेद-108
- संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है— अनुच्छेद-110
- संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है— अनुच्छेद-123
- संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है— अनुच्छेद-124
- राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है— अनुच्छेद-233
- किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं— अनुच्छेद-248
- किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है— अनुच्छेद-253
- किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है— अनुच्छेद-280
- संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है— अनुच्छेद-300 (क)
- संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोकसेवा आयोग का प्रावधान है— अनुच्छेद-315
- किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिन्दी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है— अनुच्छेद-343 (I)
- संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है— अनुच्छेद-338 (A)
- संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है— अनुच्छेद-368
- संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है— अनुच्छेद-356
- संविधान के किस अनुच्छेद में 'मंत्रिमंडल' शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है— अनुच्छेद-352
- जम्मू-कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है— अनुच्छेद-370

- अनुच्छेद-356 का संबंध किससे है— राष्ट्रपति शासन से
- भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पाँच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन-से हैं— अनुच्छेद-14-18
- संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है— अनुच्छेद-51 (क)
- 'भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार' यह कथन किस अनुच्छेद में है— अनुच्छेद-(A)
- संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है— अनुच्छेद-40
- वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं— 12
- संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किस से है— महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन-भत्तों से
- कौन-सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है— आठवीं अनुसूची
- दल-बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है— 10वीं अनुसूची
- संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है— मणिपुर
- किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है— तमिलनाडु
- भारतीय संविधान की कौन-सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है— पहली अनुसूची
- भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई— प्रथम संशोधन द्वारा
- किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है— अनुच्छेद-63
- वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है— अनुच्छेद-360
- राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है— अनुच्छेद-340
- किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है— सातवीं अनुसूची में
- समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है— जम्मू-कश्मीर से
- संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे— 47 विषय

- वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं— 66 विषय
- वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं— 97 विषय
- किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है— छठी अनुसूची में

भारतीय संविधान के स्रोत : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

- भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है— इंग्लैंड
- भारतीय संविधान का कौन-सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है— नीति-निर्देशक तत्व
- भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन-सा है— गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935
- भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है— कनाडा
- संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है— ऑस्ट्रेलिया
- भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है— रूस के संविधान से
- राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था— इंग्लैंड से
- 'कानून के समक्ष समान संरक्षण' वाक्य कहाँ से लिया गया है— संयुक्त राज्य अमेरिका से
- सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है— संयुक्त राज्य अमेरिका
- भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है— दक्षिण अफ्रीका
- 'विधि के समक्ष समता' कहाँ से ली गई है— इंग्लैंड से
- वह संवैधानिक दस्तावेज कौन-सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा— भारत सरकार अधिनियम 1935
- भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं— जर्मनी के वीमार संविधान से

- भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है— संयुक्त के वीमर संविधान से
- संविधान में 'कानून द्वारा स्थापित' शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है— संयुक्त राज्य अमेरिका
- प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है— ऑस्ट्रेलिया

भारत के संघ राज्यक्षेत्र : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

- भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है— राज्यों का संघ
- भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है— संसद को
- नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है— संसद को
- 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है— सरदार पटेल
- भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया— 1956 ई.
- भाषायी आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन-सा गठित किया गया— आंध्र प्रदेश
- राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया— 1953 ई.
- भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्रशासित प्रदेश हैं— 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश
- पांडिचेरी (वर्तमान में पुदुचेरी) को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया— 1962 ई.
- संविधान लागू होने के पश्चात कौन-सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था— सिक्किम
- किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया— 35 वें संशोधन द्वारा
- हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला— 1971 ई.
- सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया— 1975 ई.
- राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ— 1956 ई.

- रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया— सरदार पटेल के नेतृत्व में
- राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे— फजल अली
- नागालैंड को अलग राज्य को दर्जा कब प्राप्त हुआ— 1 दिसंबर, 1963 में
- राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है— अनुच्छेद-3
- भारतीय संघ में 28वाँ राज्य कौन-सा बना— झारखंड

भारतीय मूल अधिकार : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

- मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता की दी गई— संयुक्त राज्य अमेरिका
- डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा— भाग-III
- भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है— मूल संविधान का हिस्सा
- मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है— राष्ट्रपति
- मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है— सर्वोच्च न्यायालय को
- भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में हैं— अनुच्छेद-17
- मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है— व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना
- स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है— अनुच्छेद-19-22
- सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है— अनुच्छेद-19 (a)
- शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है— अनुच्छेद-21 (a)
- अनुच्छेद-24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है— बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार
- संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है— कानून अधिकार
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में हैं— अनुच्छेद-25
- मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है— संसद को
- किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है— केशवानंद भारती वाद में
- कौन-सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है— अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

- 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है— मूल अधिकार
- बी. आर. अंबेडकर ने किसे 'संविधान का हृदय एवं आत्मा' की संज्ञा दी— संवैधानिक उपचारों का अधिकार
- मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है— उच्चतम न्यायालय में
- किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है 'हम आदेश देते हैं'— परमादेश
- सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है— जम्मू एवं कश्मीर
- किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है— बन्दी प्रत्यक्षीकरण
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन-सी रिट दायर की जा सकती है— हेबियस कॉर्पस
- मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किससे पास है— संसद के पास
- प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है— भाषण स्वतंत्रता
- संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है— शोषण के विरुद्ध अधिकार
- संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया— 44 वें संशोधन द्वारा

नागरिकता : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

- भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं— अनुच्छेद-5-11
- किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है— अनुच्छेद-11
- नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है— राज्य की सदस्यता
- नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है/समाप्त हो सकती है— देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर
- भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है— ब्रिटेन
- किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है— संयुक्त राज्य अमेरिका
- भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है— एक
- संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया— 1955 ई.

● नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है— 1955 अधिनियम

● कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है— 7 वर्ष

● यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो, वह— भारत का नागरिक नहीं होगा

राज्य के नीति निर्देशक तत्व : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

● भारतीय संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है— कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना

● 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी' यह कथन किसका है— के. टी. शाह

● भारतीय संविधान का कौन-सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है— नीति-निर्देशक तत्व

● संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है— नीति-निर्देशक तत्व

● नीति-निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है— सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर

● मौलिक अधिकार व राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में क्या समानता है— ये एक-दूसरे के पूरक हैं

● क्या नीति-निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है— कुछ का हो सकता है

● समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है— राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में

● भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है— राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में

● संविधान का कौन-सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है— नीति-निर्देशक तत्व

● राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वन से है— अनुच्छेद-51

● राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है— 14 वर्ष

- भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है— गोवा
- नीति-निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है— राज्य के लिए
- समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है— अनुच्छेद

39 A

- राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में कौन-सा अधिकार शामिल नहीं है— सूचना का अधिकार

भारतीय संसद : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

- भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है— संसद
- भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है— लोकसभा + राज्यसभा + राष्ट्रपति
- संसद के कितने सदन हैं— दो
- संसद के किस सदन को 'प्रतिनिधि सभा' कहा जाता है— लोकसभा
- संसद का स्थायी सदन कौन-सा है— राज्यसभा
- भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है— राष्ट्रपति
- संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है— 6 माह
- भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है— राष्ट्रपति
- भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है— न्याय समीक्षा से
- भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है— साधारण विधेयक
- साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है— राष्ट्रपति
- स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं— चार बार
- क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है— कभी नहीं
- एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है— दो बार
- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है— लोकसभा अध्यक्ष
- संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है— राष्ट्रपति
- संसदीय प्रणाली को कौन-सी प्रथा भारत की देन है— शून्य काल
- संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन-सा होता है— प्रश्न काल

- किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है— संविधान संशोधन विधेयक
- सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है— संसद
- संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है— संघीय सरकार
- संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ— 1989 ई.
- अस्थायी संसद भारत में कब तक रही— 17 अप्रैल, 1952 ई.
- संसद भवन (पार्लियामेंट हाउस) का उद्घाटन कब हुआ— 1927 ई.
- संसद भवन (पार्लियामेंट हाउस) का उद्घाटन किसने किया था— लॉर्ड इरविन
- भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है— संसद का
- राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है— लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर
- संसद का निम्न सदन कौन-सा होता है— लोकसभा
- संसद का उच्च सदन कौन-सा होता है— राज्यसभा
- संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है— मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को

भारत के राष्ट्रपति : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

- भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है— राष्ट्रपति
- भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है— ब्रिटेन के सम्राट से
- राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं— राष्ट्रपति
- भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है— राष्ट्रपति
- भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है— राष्ट्रपति
- भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए— 35 वर्ष
- राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है— समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा
- भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है— निर्वाचन आयोग

- राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं— उच्चतम न्यायालय में
- भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है— 5 वर्ष
- राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है— संसद द्वारा महाभियोग चलाकर
- राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है— संविधान का अतिक्रमण करने पर
- राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है— अमेरिका से
- भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है— भारत का मुख्य न्यायाधीश
- संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है— अनुच्छेद-60
- राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है— उपराष्ट्रपति को
- राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है— लोकसभाध्यक्ष को
- भारत के कौन-से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे— नीलम संजीव रेड्डी
- स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे— बिहार से
- भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई— डॉ. जाकिर हुसैन
- भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है— उपराष्ट्रपति की
- वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है— राष्ट्रपति
- लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है— 14
- भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है— संघीय मंत्रीपरिषद
- कौन-सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा— एम. हिदायतुल्ला
- किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है— धन विधेयक को
- युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है— राष्ट्रपति
- किसी व्यक्ति को दोषी पाये जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है— राष्ट्रपति
- भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था— भारतीय डाकघर अधिनियम
- भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा— सर्वोच्च

न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

- अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन-सा अधिकार है— विधायी अधिकार
- भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है— सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा
- श्रीमति प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन-सी राष्ट्रपति बनी थीं— 12वीं
- कौन-से राष्ट्रपति दो बार राष्ट्रपति चुने गए— डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है— राष्ट्रपति को
- भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है— राष्ट्रपति
- भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ— संविधान सभा द्वारा
- भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है— 12
- भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है— 1,50,000 रुपए प्रतिमाह
- किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसने समय के लिए रह सकता है— 3 वर्ष
- राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है— राष्ट्रपति
- भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है— राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष
- भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है— अप्रत्यक्ष रूप से
- राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है— 50-50
- भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है— राष्ट्रपति के चुनाव में
- राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है— 6 माह में
- भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है— राज्यपाल
- राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है— संघ व समवर्ती सूची पर
- जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है— राष्ट्रपति की अनुमति के बाद

भारत के उपराष्ट्रपति : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

- भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है— संयुक्त राज्य अमेरिका
- राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है— उपराष्ट्रपति
- राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है— उपराष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है— अप्रत्यक्ष रूप से
- उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन-सा प्रणाली अपनाई जाती है— एकल संक्रमणीय प्रणाली
- उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है— राष्ट्रपति
- भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है— संसद के दोनों सदन
- उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है— राष्ट्रपति को
- उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है— मतों के बराबर रहने की स्थिति में
- भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे— सर्वपल्ली राधाकृष्णन
- कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है— संसद को
- किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है— राज्यसभा में
- भारत में लगातार दो बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था— सर्वपल्ली राधाकृष्णन
- मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन-से उपराष्ट्रपति हैं— 12वें
- उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं— 20
- उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है— सर्वोच्च न्यायालय
- उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है— 5 वर्ष
- उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है— 35 वर्ष
- उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है— लोकसभा अध्यक्ष के समान
- संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है— अनुच्छेद-63 में
- उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता— राज्यसभा का

राज्यसभा : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

- वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है— 245
- राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है— विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
- राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है— राज्य की जनसंख्या पर
- राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है— उत्तर प्रदेश
- राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है— 6 वर्ष
- राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए— 30 वर्ष
- किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है— राज्यसभा
- लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है— कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग
- वह कौन-सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है— राज्यसभा
- लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है— 14 दिन
- राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्यों— क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं
- राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है— राष्ट्रपति को
- राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी— वी. एस. रमादेवी
- राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ— 3 अप्रैल, 1952 ई.
- राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई— 13 मई, 1952 ई.
- भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है— संसद
- राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है— उपसभापति
- राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों को अधिसूचना कौन जारी करता है— निर्वाचन आयोग
- केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है— राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत पर
- राज्यसभा की दो बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना चाहिए— अधिकतम 6 माह
- किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है— अंडमान-निकोबार, चंडीगढ़, दादरा-नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन-दीव

- राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है— मंत्रीपरिषद
- भारत के कौन-से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं— श्रीमति इंदिरा गाँधी व मनमोहन सिंह

लोकसभा : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

- जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं— लोकसभा
- संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है— 552
- वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं— 545
- राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है— दो
- लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है— जनसंख्या के आधार पर
- वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है— 1971 की जनगणना पर
- कौन-सी लोकसभा के चुनाव चार चरणों में हुए— 14वीं
- लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए— 25 वर्ष
- कौन-सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है— उत्तर प्रदेश
- किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं— आंध्र प्रदेश व पश्चिमी बंगाल
- उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है— महाराष्ट्र में
- किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है— नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम
- लोकसभा का नेता कौन होता है— प्रधानमंत्री
- लोकसभा का नेता कौन होता है— लोकसभा अध्यक्ष को
- भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई— 1976 ई.
- लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं— वर्ष में दो बार
- लोकसभा को कौन भंग कर सकता है— राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर
- वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है— लोकसभा में
- अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है— लोकसभा
- बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है— लोकसभा द्वारा
- लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है— लोकसभा अध्यक्ष

- अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं— प्रोटेम स्पीकर
- प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है— राष्ट्रपति
- कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है— 2 माह
- किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है— वित्त विधेयक
- मंत्रीपरिषद् किसके प्रति उत्तरदायी होती है— लोकसभा के
- किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है— आपातकाल की स्थिति में
- संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है— 1 वर्ष के लिए
- किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक-एक करके दो बार बढ़ाया गया— 1976 में
- राजनीतिक शब्दावली में 'शून्य काल' का अर्थ क्या है— प्रश्नोत्तर सत्र
- यदि कोई व्यक्ति राजसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है— हाँ

भारत के प्रधान मंत्री व मंत्रीपरिषद् : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

- भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है— राष्ट्रपति
- योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है— प्रधानमंत्री
- संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है— प्रधानमंत्री
- प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है— 5 वर्ष
- प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे— मोरारजी देसाई
- कौन-से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे— जवाहर लाल नेहरू
- प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है— 25 वर्ष
- संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किसे देश में लागू हुई— ब्रिटेन
- भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है— प्रधानमंत्री में
- भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे— जवाहर लाल नेहरू
- अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है— तीन
- प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है— राष्ट्रपति
- किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था— इंदिरा

गाँधी

- जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने— गुजजारी लाल नंदा
- संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है— प्रधानमंत्री के पास
- सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने— राजीव गाँधी
- लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है— प्रधानमंत्री
- किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे— एच. डी.

देवगौड़ा

- कौन-से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए— चौ. चरण सिंह
- यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है— मंत्रिपरिषद में
- संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं— लोकसभा के
- भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकती है— 6 माह
- संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है—

अनुच्छेद-75

- मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है— केंद्रीय मंत्री
- स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे— डॉ. बी. आर. अंबेडकर
- कौन-सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है— विश्वास प्रस्ताव
- मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है— राष्ट्रपति
- भारत के मंत्रिपरिषद् में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिये जाते हैं— लोकसभा से
- स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे— सरदार पटेल
- स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त कौन थे— डॉ. जॉन मथाई
- क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है— हाँ

लोकसभा अध्यक्ष : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

- लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है— लोकसभा सदस्य
- लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है— राष्ट्रपति
- लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है— लोकसभा उपाध्यक्ष को

- निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है— लोकसभा अध्यक्ष को
- लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है— लोकसभा अध्यक्ष
- भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे— जी. वी. मावलंकर
- भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है— लोकसभा अध्यक्ष
- लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है— लोकसभा अध्यक्ष
- किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है— नियम समिति
- लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है— लोकसभा स्पीकर
- कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया— के. एस. हेगड़े
- लोकसभा का जनक किसे माना जाता है— जी. वी. मावलंकर
- लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे— अनंतशयनम आपंगर
- किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा— बलराम जाखड़
- लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है— लोकसभा का वरिष्ठतम् सदस्य
- राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है— लोकसभा महासचिव
- भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाऊस ऑफ कॉमंस के अध्यक्ष की तरह होते हैं— इंग्लैंड के
- लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है— लोकसभा अध्यक्ष
- भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं— मीरा कुमार

कैग (नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक) : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

- निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है— राष्ट्रपति
- प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है— जनता द्वारा मतदान
- निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है— अनुच्छेद-324
- भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है— ब्रिटेन से

- मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है— निर्वाचन आयोग का
- निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है— मुख्य निर्वाचन आयुक्त
- परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है— मुख्य निर्वाचन आयुक्त
- मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर कौन रखता है— निर्वाचन आयोग
- भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे— सुकुमार सेन
- भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ— 1952 ई.
- भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ— 1989 ई.
- भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है— 18 वर्ष
- चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद होता है— चुनाव से 48 घंटे पहले
- निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है— राष्ट्रपति को
- निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति किसकी सलाह पर पदच्युत करता है— मुख्य निर्वाचन आयुक्त की
- निर्वाचन आयुक्त की सेवाशर्त/कार्यकाल कौन निश्चित करता है— संविधान
- लोकसभा/विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जव्त कर ली जाती है— मतदान का 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर
- निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है— 5 वर्ष के लिए
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है— महाभियोग द्वारा
- विधान परिषद् के चुनावों का संचालन कौन करता है— निर्वाचन आयोग
- दिनेश गोस्वामी समिति किस से संबंधित है— निर्वाचन आयोग से
- चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है— निर्वाचन आयोग
- इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था— चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष व्यवस्था

भारत का उच्चतम न्यायालय : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

- संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है— सर्वोच्च न्यायालय
- संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है— भाग-V
- किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई— रेग्युलेटिंग एक्ट 1773
- संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था

सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी— 7

- उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है— संसद को
- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है— 31
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है— राष्ट्रपति
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है— 65 वर्ष की आयु तक
- सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियाँ व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है— अमेरिका
- क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं— नहीं
- किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाती बनाया गया है— अनुच्छेद-143
- न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है— स्वतंत्र
- सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है— संचित निधि से
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है— महाभियोग द्वारा
- भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे— हरिलाल जे. कानिया
- किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है— अनुच्छेद-129
- सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी— केशवानंद भारतीवाद में
- जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है— सर्वोच्च न्यायालय में
- यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है— वाई. वी. चंद्रचूड़
- सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है— जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या वह 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो
- मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है— सर्वोच्च न्यायालय

भारतीय उच्च न्यायालय : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

- भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं— 21
- भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है— सिक्किम उच्च न्यायालय
- भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है— इलाहाबाद उच्च न्यायालय
- भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन-सा है— इलाहाबाद उच्च न्यायालय
- पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई— 1916 ई.
- मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है— जबलपुर
- उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है— भारतीय संसद को
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है— राष्ट्रपति
- उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है— 65 वर्ष की आयु तक
- उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थीं— श्रीमती लीला सेठ
- किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है— राष्ट्रपति को
- भारत का चलित न्यायालय किसका मानसंपुज है— डॉ. ए.पी.जे. कलाम आजाद
- किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक स्थाई/अस्थायी खंडपीठ है— गुवाहटी उच्च न्यायालय में
- केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है— एर्नाकुलम
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है— राज्यपाल
- संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है— अनुच्छेद-226

- ओड़िशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है— कटक
- किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है— संबंधित राज्य की लोकलेखा निधि से
- केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है— दिल्ली में

राज्यपाल : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

- किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है— राज्यपाल में
- राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है— राष्ट्रपति
- किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है— राज्यपाल को
- राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है— 5 वर्ष
- राज्यपाल का वेतन-भत्ता किस कोष से आता है— राज्य की संचित निधि द्वारा
- राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है— राज्यपाल
- राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है— राष्ट्रपति को
- राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है— राज्यपाल
- कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बना रहता है— राज्यपाल
- राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है— 35 वर्ष
- राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल-भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है— एक
- भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी— सरोजनी नायडू
- 'राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है' ये शब्द किसके हैं— सरोजनी नायडू
- किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है— राज्यपाल
- राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है— विधानमंडल द्वारा
- राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है— राज्यपाल
- राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है— राज्यपाल
- राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है— केंद्र व राय के मध्य की कड़ी

- किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है— उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश
- किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है— जम्मू-कश्मीर
- भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनीं— उत्तर प्रदेश
- जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है— 6 माह
- जम्मू-कश्मीर का 'सदर-ए-रियासत' पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया— 1965 में
- राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है— राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति

पंचायती राज व्यवस्था : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

- संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है— भाग-9
- पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है— सत्ता के विकेंद्रीकरण पर
- पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है— जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना
- किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है— नीति-निर्देशक सिद्धांत
- संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है— 75वें संशोधन
- 75वें संशोधन में कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई हैं— 11वीं
- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है— राज्य निर्वाचन आयोग
- भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ— 25 अप्रैल, 1993
- सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई— नागौर, राजस्थान में
- राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई— 1959 को
- देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन-सा कार्यक्रम चलाया गया— सामुदायिक विकास कार्यक्रम
- भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ— 2 अक्टूबर, 1952
- किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई— बलवंत राय मेहता समिति

- पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है— ग्राम पंचायत
- बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन-सी है— पंचायत समिति
- पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के दो स्तर होने का सुझाव किसने दिया था— अशोक मेहता समिति
- पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है— ग्राम प्रधान
- पंचायती राज विषय किस सूची में है— राज्य सूची में
- किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गईं— 73वें संशोधन में
- पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए— 21 वर्ष
- पंचायती राज संस्थाएँ अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं— सरकारी अनुदान पर
- एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है— एक प्रशासकीय अभिकरण
- भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ— चेन्नई
- ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है— मेला व बाजार कर
- किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है— अरुणाचल प्रदेश में
- पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है— ग्राम स्तर पर
- पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है— 5 वर्ष
- 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया— प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान
- पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है— राज्य सरकार
- पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है— प्रखंड स्तर पर
- यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है— 6 माह

भारतीय संविधान के संशोधन

- पहला संशोधन (1951) —इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
- दूसरा संशोधन (1952) —संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
- सातवां संशोधन (1956) —इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।

- दसवां संशोधन (1961) —दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
- 12वां संशोधन (1962) —गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
- 13वां संशोधन (1962) —संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
- 14वां संशोधन (1963) —पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
- 21वां संशोधन (1967) —आठवीं अनुसूची में 'सिंधी' भाषा को जोड़ा गया।
- 22वां संशोधन (1968) —संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद् का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
- 24वां संशोधन (1971) —संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
- 27वां संशोधन (1971) —उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक 'पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्' की स्थापना की गई।
- 31वां संशोधन (1974) —लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई। इनमें से 545 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
- 36वां संशोधन (1975) —सिक्किम को भारतीय संघ में संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया।
- 37वां संशोधन (1975) —अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
- 42वां संशोधन (1976) —इसे 'लघु संविधान' (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
—इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष', 'समाजवादी' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए।
—इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल

कर्तव्य निश्चित किए गए।

—लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।

—नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।

—इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।

—यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।

—संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।

● 44वां संशोधन (1978) —संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।

—लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।

—राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।

— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।

—‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।

● 52वां संशोधन (1985) —इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।

● 55वां संशोधन (1986) —अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान किया गया।

● 56वां संशोधन (1987) —इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।

● 61वां संशोधन (1989) —मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

● 65वां संशोधन (1990) —‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।

● 69वां संशोधन (1991) —दिल्ली का नाम ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली’ किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का

प्रावधान किया गया।

- 70वां संशोधन (1992) —दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया।
- 71वां संशोधन (1992) —तीन और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया।
- 73वां संशोधन (1992) —संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- 74वां संशोधन (1993) —संविधान में एक नया भाग 9क और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- 91वां संशोधन (2003) —इसमें दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया।
- 92वां संशोधन (2003) —इसमें आठवीं अनुसूची में चार और भाषाओं-मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया।
- 93वां संशोधन (2005) —इसमें एससी/एसटी व ओबीसी बच्चों के लिए गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया।
- 97वां संशोधन (2011) —इसमें संविधान के भाग 9 में भाग 9ख जोड़ा गया और हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार दिया गया।